विकास और किसान

लेखक- अशोक गुलाटी (प्रोफ़ेसर, ICRIER)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

16 मार्च, 2020

"विकास और किसानः खाद्य नीति में उपभोक्ता पूर्वाग्रह किसानों के लिए प्रोत्साहन को कम करता है।"

पिछले महीने, मोंटेक सिंह अहलूवालिया की किताब, बैकस्टेजः द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ इयर्स का विमोचन किया गया था। यह भारत की आर्थिक सुधार यात्रा का एक लेखा-जोखा है। मोंटेक के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन से संबंधित कुछ बहुत ही रोचक प्रकरणों के अलावा, यह पुस्तक नीतिगत बहस और उनकी जटिलताओं में उपयोगी अंतर्दृष्टि से भरी हुई है। कई स्थानों पर, यह इन नीतियों के प्रभाव का प्रमाण प्रस्तुत करती है। यह अत्यंत उपयोगी हो सकता है क्योंकि हम देश की सुस्त अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करने और गरीबी को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। पुस्तक में शामिल हर मुद्दे के साथ न्याय करना असंभव है। यहाँ, मैं (लेखक) खुद को कृषि-खाद्य क्षेत्र में नीतिगत बहस और विकल्पों तक सीमित करूँगा।

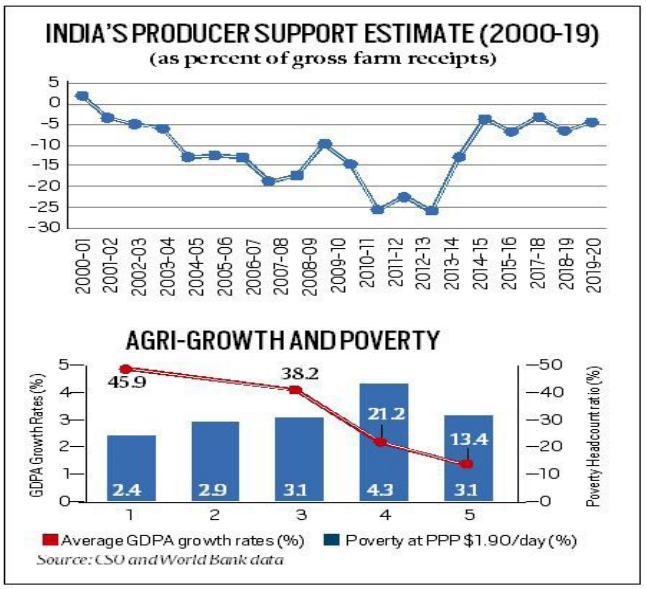

समावेशी विकास के तहत कृषि रणनीति दिखाई देती है। यूपीए की अवधि के दौरान, 2004-05 से 2013-14 तक यह माना जाता था कि समावेशी विकास संभव नहीं है, जब तक कि कृषि प्रति वर्ष लगभग 4 प्रतिशत की दर से न बढ़े, जबकि समग्र अर्थव्यवस्था सालाना लगभग 8 प्रतिशत की दर से बढ़ती है। इसका कारण सरल था, अर्थात उस समय काम करने वाले आधे से अधिक बल कृषि में लगे हुए थे और उनकी अधि कांश आय कृषि से प्राप्त होती थी। लेकिन कांग्रेस के भीतर भी कई राजनीतिक दिग्गजों ने यह नहीं माना कि कृषि-विकास गरीबी को काफी तेजी से कम कर सकता है।

कृषि रणनीति का मुख्य साधन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) था, जो राज्यों को कृषि से संबंधित योजनाओं के भीतर संसाधनों का आवंटन करने के लिए अधिक लाभ देता था। यह, ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य बुनियादी ढाँचे के निवेश के साथ, कृषि-विकास पर लाभकारी प्रभाव था, जो वाजपेयी अवधि (1998-99 से 2003-04) के दौरान 2.9 प्रतिशत से बढ़कर यूपीए-1 अवधि (2004-05 जव 2008-09) के दौरान 3.1 प्रतिशत हो गया और यूपीए-2 (2009-10 से 2013-14) के दौरान 4.3 प्रतिशत हो गया। मेरा दृढ़ता से मानना है कि UPA-2 के दौरान UPA-2 के दौरान कृषि-सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि RKVY द्वारा संचालित नहीं थी।

कृषि-जीडीपी वृद्धि का गरीबी में कमी पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, इसे जिस भी तरीके से मापा गया (लकड़ावाला गरीबी

रेखा या तेंदुलकर गरीबी रेखा) यह अधिक ही रहा। गरीबी में गिरावट की दर, 1993-94 से 2004-05 के दौरान प्रति वर्ष लगभग 0.8 प्रतिशत से प्रति वर्ष 2.1 प्रतिशत तक बढ़ गई और पहली बार गरीबों की पूर्ण संख्या में 2004-05 से 2013-14 के दौरान गरीबों की निरपेक्ष संख्या में 138 मिलियन की गिरावट आई। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रति दिन + 1.9 प्रति व्यक्ति की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर भी है (2011 में क्रय शक्ति समता, पीपीपी, निचे दिए ग्राफ देखें)।

हालाँकि, गरीबी उन्मूलन में विकास की इस रणनीति की सफलता का जश्न मनाने के बजाय, कई गैर-सरकारी संगठन और यहाँ तक कि कांग्रेस के समर्थक संशयात्मक रहे। उन्होंने राईट टू फूड अभियान के तहत खाद्य सब्सिडी की वकालत की। सोनिया गांधी और उनकी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) ने 90 फीसदी लोगों को चावल और गेहूँ क्रमशः 3 रुपये किलो और 2 रुपये किलो की दर से सब्सिडी देने का प्रस्ताव पेश किया। मोंटेक ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इससे सरकारी खजाने पर एक अनिश्चित बोझ पैदा होने की संभावना है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि भारत प्रति वर्ष 13-15 मिलियन टन अनाज के आयात को समाप्त कर सकता है। मोंटेक ने 2011-12 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 40 प्रतिशत आबादी पर कैप का समर्थन किया, क्योंकि गरीबी अनुपात (HCR) 22 प्रतिशत था। उन्होंने लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड प्रदान करने का भी समर्थन किया ताकि वे चावल और गेहूँ पर निर्भर रहने के बजाय अधिक पौष्टिक भोजन खरीदने का विकल्प चुन सकें। इन्होंने कृषि और संवर्धित किसानों की आय में विविधता लाने की भी अनुमति दी। लेकिन वह NAC पर जीत हासिल नहीं कर सके - हालाँकि खाद्य सब्सिडी के कवरेज को 90 प्रतिशत के मूल प्रस्ताव से घटाकर 67 प्रतिशत आबादी कर दिया गया। मोंटेक ने कृषि उत्पाद निर्यात पर प्रतिबंध के खिलाफ भी तर्क दिया क्योंकि इससे किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जब हम वर्षों बाद OECD पद्धति (वैश्विक कृषि-उत्पादन का 70 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करने वाले देशों द्वारा उपयोग किया जाता है) के अनुसार निर्माता समर्थन अनुमान (PSE) का अनुमान लगायेंगे तब हमें एक नकारात्मक PSE मिलेगा। यह व्यापार और विपणन नीतियों के माध्यम से कृषि के अंतर्निहित कराधान को इंगित करता है। (पीएसई ग्राफ देखें)

आज केंद्रीय बजट के कृषि-खाद्य क्षेत्र में खाद्य सब्सिडी सबसे बड़ी वस्तु है। मौजूदा बजट में, यह 1,15,570 करोड़ रुपये का प्रावधान करता है। हाल ही में, सरकार भारतीय खाद्य निगम (FCI) से असंख्य स्रोतों से उधार लेने के लिए कह रही है और पूरी तरह से खाद्य सब्सिडी का वित्तपोषण नहीं कर रही है, जो तार्किक रूप से एक बजटीय वस्तु होनी चाहिए। एफसीआई पर बकाया उपबंधित सब्सिडी से अधिक है और यदि कोई इन बकाए को बजटीय खाद्य सब्सिडी में जोड़ता है, तो खाद्य सब्सिडी की प्रभावी राशि 3,57,688 करोड़ रुपये हो जाती है। यह सिस्टम में उपभोक्ता के पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है।

2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण खाद्य सब्सिडी को 20 प्रतिशत आबादी तक सीमित करता है, जिसमें 2015 में विश्व बैंक की + 1.9 / प्रति दिन प्रति व्यक्ति (पीपीपी) के अनुसार गरीबी की गणना केवल 13.4 प्रतिशत थी। दूसरों के लिए, चावल और गेहूँ की कीमतों को खरीद मूल्य के कम से कम 50 प्रतिशत या इससे भी बेहतर एफसीआई की आर्थिक लागत का 50 प्रतिशत से जुड़ा होना चाहिए। जब तक हम इस मोर्चे पर प्रगति नहीं करते हैं, कृषि के विकास के लिए संसाधनों को अनलॉक करना मुश्किल है, जोकि मोदी 1.0 के दौरान यूपीए-2 के दौरान 4.3 प्रतिशत से घटकर 3.1 प्रतिशत हो गया।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'बैकस्टेज़: द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज़ हाई ग्रोथ ईयर्स' नरेन्द्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
2. लकड़वाला तथा तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements:

1. 'Backstage: The Story Behind India's High Growth Years' is a book written by Narendra Modi.
2. Lakdawala and Tendulkar Committee are related to the determination of poverty line.

Which of the above statements is / are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) None of these

नोट : 14 मार्च को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 'कृषि क्षेत्रक का विकास कृषि जिंसों के मूल्य वृद्धि, कृषि को लेकर अधिक बजटीय आवंटन आदि पर निर्भर करता है।' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द)

Development of agriculture sector depends on price rise of agricultural commodities, more budgetary allocation for agriculture, etc.' Do you agree with this statement? Comment. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।